International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 15 Issue 2 || February 2026 || PP. 256-267

डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कौशल विकास और रोजगार सृजन: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

शोधार्थी – स्नेह लता दीक्षित

अर्थशास्त्र

छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर

snehachaturvedi.2000@gmail.com

डॉ (प्रो.) तेजपाल सिंह

विद्या मंदिर महाविद्यालय,कायमगंज,फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

डॉ (प्रो.) रश्मि प्रियदर्शनी

बद्री विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

सारांश

वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के द्वारा शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका आज के युवाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक हो रही है, बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार कर रही है। जिसमें ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल ट्रेनिंग, ई-लर्निंग मॉड्यूल और मोबाइल एप्स के माध्यम से शिक्षार्थी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर आवश्यक कौशल सीख सकते हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच की दूरी में कमी आयी है परिणामस्वरूप सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मुख्य रूप से ग्रामीण, महिला और कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान किए हैं जिससे कौशल और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहन दिया है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के अनुरूप है। डिजिटल माध्यमों से प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक लचीले, किफायती और प्रभावी हो गए हैं। साथ ही, उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी आसान हो गया है। सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर कौशल विकास अभियानों को गति प्रदान की जा रही है। फलस्वरूप इससे न केवल बेरोज़गारी में कमी आयी है बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी भारत अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी और प्रभावी बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

मुख्य शब्दकोश *- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, कौशल विकास, रोजगार उन्मुख शिक्षा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वर्चुअल लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक विकास।*

प्रस्तावना -

विश्व के बदलते आर्थिक परिदृश्य में एक ऐसी क्रांति का जन्म हुआ है, जिसने किसी राष्ट्र की उन्नति को केवल भौतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी जनता के ज्ञान, कौशल और तकनीकी दक्षता से मापा है। हम सब आज उस देश के नागरिक हैं,जहाँ राष्ट्रों की शक्ति उनके प्राकृतिक भंडार से कम और मानव संसाधन की गुणवत्ता से अधिक आंकी जा रही है। ऐसे युग में कौशल विकास महज एक शब्द नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार, उसके सपनों का मार्ग और राष्ट्र के भविष्य का ध्वजवाहक बन गया है। भारत, जिसे विश्व की सबसे युवा आबादी वाला राष्ट्र कहकर संबोधित किया जाता है। उसके सामने यह समय एक बड़ी चुनौती और एक अद्भुत अवसर दोनों ही बनकर खड़ा है। करोड़ों की संख्या में युवा ऊर्जा, आकांक्षा, उत्साह और अपार संभावनाएँ लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा मंच मिले जहाँ वे अपनी क्षमताओं को गढ़ सकें, निखार सकें और उन्हें रोजगार एवं समृद्धि में परिवर्तित कर सकें। डिग्री प्राप्त करने के बाद भी लाखों युवक-युवतियाँ रोजगार की तलाश में इधर -उधर भटकते हैं, क्योंकि उनके पास

बाजार की वास्तविक आवश्यकता से जुड़ा कौशल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता थी तो बस एक ऐसे विचार की जिससे समावेशी विकास की राह तय की जाए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आयी तो सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में श्रम बल की अधिकता है। युवा रोजगार की तलाश में तो हैं लेकिन कौशल के अभाव में बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। इन परिस्थितियों में सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद विचार को अपनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जनपद से 25 कि. मी. कि दूरी पर स्थित नगला चंद्रभान गाँव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं समाजसुधारक थें। एकात्म मानववाद का अर्थ है समग्र विकास व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र का विकास करना। इसी विचार को सरकार ने व्यावहारिक रूप देना प्रारंभ किया। यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानव, समाज और राष्ट्र—तीनों का संतुलित एवं समन्वित विकास होना चाहिए।

- व्यक्ति का विकास ⟶ कौशल, शिक्षा, आत्मनिर्भरता
- समाज का विकास ⟶ समान अवसर, समावेशिता
- राष्ट्र का विकास ⟶ संतुलित और सतत प्रगति

इस विचार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त होने चाहिए जिससे वह वह आत्मनिर्भर बने और समाज के विकास में योगदान दे। सरकार इसी ने इसी विचार को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया। सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुवात की। धीरे – धीरे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगमन हुआ। नीति निर्माता यह जानते थें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ही एक ऐसी जगह है जिसके माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि लोगों में कौशल होगा तो रोजगार और स्व रोजगार के नए -नए मार्ग स्वतः ही खुल जाएंगे। इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास की परिभाषा ही बदल गयी है। प्रौद्योगिकी के इस अद्भुत युग में एक मोबाइल फोन या लैपटॉप मात्र ज्ञान का दरवाज़ा नहीं, बल्कि भविष्य के अनगिनत अवसरों की चाबी की भांति है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह गाँव का लड़का हो या महानगर की लड़की, चाहे वह नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या घर संभालने वाली महिला अब अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी गति से, अपनी पसंद के अनुसार कौशल को सीख सकता है। यह शिक्षा अब किसी बंधनों में नहीं है यह स्वतंत्र है, खुली है, गतिशील है और अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। भारत के ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मात्र एक तकनीक नहीं, बल्कि एक आशा की किरण की तरह है। वे जो कभी सोचते थे कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा केवल बड़े शहरों, महंगे कॉलेजों या प्रतिष्ठित संस्थानों में ही मिल सकती है, आज वही युवा अपने घर में बैठकर SWAYAM, NPTEL, e-Skill India, DIKSHA, Coursera, Udemy और अनगिनत डिजिटल मंचों से वह सब सीख पा रहे हैं, जो कभी उनकी पहुँच से बाहर था। इस परिवर्तन को महज सुविधा नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति कहना चाहिए । जब व्यक्ति डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर कौशल अर्जित कर रोजगार प्राप्त करता है या स्वरोजगार स्थापित करता है तो वह स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ – साथ औरों को भी आत्मनिर्भर करता है। यही आत्मनिर्भर, व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की आधारशिला बनता है। सरकार लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद एवं आत्मनिर्भर भारत के विचार को केंद्र में रख कर आगे बढ़ती रही है। भारत सरकार ने Skill India Mission, Digital India, PMKVY, e-Skill India और अन्य कार्यक्रमों ने डिजिटल माध्यमों को एक सशक्त ढांचा प्रदान किया है। यह प्रयास न केवल शिक्षण को आधुनिक बना रहे हैं, बल्कि भारत को एक वैश्विक कौशल केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम भी उठा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की मुख्य भूमिका तो उस समय समझ आयी,जब महामारी के समय COVID-19 के दौरान जब देशभर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हो गए, भौतिक शिक्षा व्यवस्था ठप्प हो गयी तब शिक्षा और कौशल विकास की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित हुई। लाखों छात्रों और युवाओं ने डिजिटल कोर्स के माध्यम से अपने कौशल का विकास किया और नए अवसरों की दिशा में कदम भी बढ़ाए। इससे यह सिद्ध हो गया कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म न केवल वैकल्पिक बल्कि भविष्य की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। भारत में तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने न केवल युवाओं को सीखने के महत्वपूर्ण अवसर दिए हैं बल्कि उन्हें उद्यमिता की दिशा में भी प्रेरित किया है। आज अनेक युवा डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं, जिससे नए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। यह परिवर्तन भारत को एक 'कौशल संपन्न राष्ट्र' बनाने की दिशा में ठोस कदम है क्योंकि जब व्यक्ति कौशल विकास के माध्यम स्वयं रोजगार प्राप्त करने या सृजित करने में सक्षम हो जाता है, तब वह मात्र आर्थिक इकाई नहीं रह जाता, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन का भी वाहक बन जाता है। यह वही प्रक्रिया है जो व्यापक स्तर पर समावेशी विकास को जन्म देती है, जिससे विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक आसानी से पहुँचते हैं। अतः यहाँ मैं यह निःसंकोच कह सकती हूँ कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म वर्तमान समय में एक ऐसे सेतु के रूप में कार्य कर रहा है, जो तकनीकी प्रगति को मानवीय विकास और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ता हैं, और इसी में एकात्म दृष्टिकोण की वास्तविक अभिव्यक्ति भी निहित है।

भारत में डिजिटल शिक्षा का विकास

भारत में डिजिटल शिक्षा का इतिहास किसी एक क्षण मात्र में नहीं बना, बल्कि यह अनेक छोटे-बड़े प्रयासों, प्रयोगों और नीतिगत सुधारों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। प्रारंभिक चरणों में तकनीक को शिक्षा के साथ जोड़ने का उद्देश्य केवल पारंपरिक शिक्षण को सहायक बनाना था। परन्तु समय के साथ-साथ यह प्रयास एक व्यापक डिजिटल शिक्षण–व्यवस्था का रूप लेता गया, जिसने सीखने की प्रक्रिया, पहुँच और अवसर— तीनों को नए आकार के रूप में परिभाषित किया गया । आज डिजिटल शिक्षा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की शिक्षा का आधार स्तम्भ बन रही है, जो अधिक समावेशी, लचीली, बहु-स्तरीय और कौशल-केन्द्रित है। डिजिटल शिक्षा की यह यात्रा उस बदलाव का प्रतीक हम कह सकते हैं, जिसमें भारतीय शिक्षा पारम्परिक ढाँचों से निकलकर तकनीकी-समर्थित, खुली तथा बहु-आयामी प्रणाली की ओर बढ़ी। सरकार के प्रयास, तकनीकी विस्तार, इंटरनेट का प्रसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और वैश्विक शैक्षिक प्रवृत्तियों ने मिलकर ऐसा वातावरण बनाया, जहाँ सीखना केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल माध्यमों के द्वारा हर शिक्षार्थी के हाथों तक पहुँच चुका है।

डिजिटल शिक्षा में SWAYAM का योगदान

2017 में भारत सरकार ने **SWAYAM** नामक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य "सबके लिए शिक्षा" की अवधारणा को वास्तविकता बनाना था। SWAYAM में प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के कोर्स उपलब्ध कराए गए, जिनमें देश के सर्वोत्तम संस्थानों द्वारा निर्मित पाठ्य सामग्री सम्मिलित थी। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह मंच शिक्षा के अवसरों का वास्तविक लोकतंत्रीकरण साबित हो रहा है ।

स्मार्टफोन और इंटरनेट क्रांति : डिजिटल शिक्षा के नया अध्याय का प्रारंभ

भारत में डिजिटल शिक्षा का वास्तविक विस्तार तब संभव हुआ, जब स्मार्टफोन सस्ता हुआ और 4G इंटरनेट का व्यापक प्रसार हुआ। Digital India अभियान ने भी इंटरनेट की सार्वजनिक पहुँच को तेजी से गति दी। इन सुविधाओं ने करोड़ों लोगों को शिक्षा के नए, आधुनिक और सुगम माध्यमों से जोड़ दिया। आज भारत का एक बड़ा वर्ग मोबाइल आधारित एप्स और डिजिटल प्लेटफार्मों के जरिए अपने समय, गति और आवश्यकता के अनुसार सीख पा रहा है।Byju's, Unacademy, Vedantu आदि प्लेटफार्मों ने व्यक्तिगत शिक्षण (personalized learning), टेस्ट-सीरीज, डिजिटल नोट्स, इंटरएक्टिव कक्षाओं और AI- आधारित फीडबैक सिस्टम को लोकप्रिय बनाया। AI-powered learning paths ने सीखने को अधिक परिणाम-उन्मुख बनाया, जहाँ प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और आवश्यकता के आधार पर सामग्री बदलती रहती है। जिसने शिक्षा के क्षेत्र को विस्तारित किया

भारत में डिजिटल शिक्षा का रोजगार पर प्रभाव

भारतीय सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं **NMEICT (National Mission on Education through ICT)** ने डिजिटल अधो-संरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया। **DIKSHA Portal**, **e-Pathshala**, **National Digital Library**, **Virtual Labs** जैसे प्रयासों ने छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए संसाधनों को सरलता से उपलब्ध कराया। निजी कंपनियों—Microsoft, Google, Amazon Web Services ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्लाउड-आधारित समाधान, डिजिटल कंटेंट निर्माण और शिक्षकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन साझेदारियों ने डिजिटल शिक्षा के विकास की गति को कई गुना बढ़ाया। MOOCs और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सों ने कार्यरत युवाओं और पेशेवरों के लिए कौशल विकास को अधिक लचीला और सुलभ बनाया, जिससे रोजगार-उन्मुख सीखने का दायरा लगातार विस्तृत हुआ। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और उद्योगों में तेज़ी से बदलती कौशल-आवश्यकताओं ने ऐसे मानव संसाधन की माँग बढ़ा दी है, जो तकनीकी दक्षताओं के साथ-साथ विश्लेषणात्मक और सॉफ्ट स्किल्स में भी निपुण हों। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने लाखों लोगों को न केवल नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सीखना किसी समय या स्थान की बाधा में न बँधे। आज डिजिटल शिक्षा भारत की कौशल अर्थव्यवस्था का वह स्तम्भ बन चुकी है, जो रोजगार-उन्मुख सीखने, कार्य-तैयारी और सतत् कौशल-विकास को नई दिशा दे रही है। विभिन्न अध्ययनों और प्लेटफॉर्म रिपोर्टों ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल कोर्स करने वाले शिक्षार्थियों की—रोजगार पाने की संभावनाएँ बढ़ी हैं**,** कैरियर में उन्नति तेज होती है। Coursera की रिपोर्टों के अनुसार Professional Certificates पूरा करने वाले शिक्षार्थियों में एक बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का है, जिन्हें नया रोजगार मिला या उन्हें उच्च पद प्राप्त हुआ।

डिजिटल शिक्षा कौशल-अंतर को पाटने का सबसे प्रभावी माध्यम

भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने कौशल-आधारित प्रशिक्षण को बड़े पैमाने पर डिजिटल माध्यमों से सुलभ बनाया है।यह योजना ग्रामीण युवाओं,महिलाओं,आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कुशल बनाकर रोजगार योग्य बनाने में अत्यंत सहायक रही है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स के सहयोग से उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण तैयार किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग से PMKVY का विस्तार, निगरानी और प्रमाणन अधिक प्रभावी हुआ है। भारत में कौशल-अंतर (Skill Gap) की सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि उद्योगों की मांगे जिस गति से बदल रही थीं, पारंपरिक संस्थान उनकी पूर्ति के लिए तैयार नहीं थे। डिजिटल शिक्षा ने इस समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया। Coursera, edX, Udemy, Simplilearn, LinkedIn Learning जैसे प्लेटफ़ॉर्म—डेटा साइंस,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,मशीन लर्निंग,डिजिटल मार्केटिंग,क्लाउड कंप्यूटिंग,साइबर सुरक्षा,सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे उच्च माँग वाले कौशलों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। इन प्लेटफॉर्मों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी अपनी गति से, अपने समयानुसार सीख सकते हैं। कामकाजी पेशेवर बिना नौकरी छोड़े अपस्किल और रिस्किल कर सकते हैं। सीखने की यह लचीलापन और वैश्विक विशेषज्ञता तक पहुँच पारंपरिक शिक्षा नहीं दे पाती। Coursera द्वारा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, edX का MIT और Harvard द्वारा सह-स्थापित होना, तथा Udemy का विशिष्ट विषय-विशेषज्ञों द्वारा कोर्स निर्माण इन सभी ने सीखने की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया है।

शोध उद्देश्य (Research Objectives)

1. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उन्मुख शिक्षा में अंतर और प्रगति को समझना।
2. ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल ट्रेनिंग, ई-लर्निंग मॉड्यूल और मोबाइल एप्स किस प्रकार युवाओं को कौशल विकसित करने और रोजगार के लिए तैयार करने में सहायक है।
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), Skill India Mission, e-Skill India, SWAYAM आदि कार्यक्रमों का रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन।
4. डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भरता में पंडित दीदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद'सिद्धांत का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि - इस अध्ययन में मात्रात्मक (quantitative) और गुणात्मक (qualitative) दोनों विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए द्वितीयक डेटा (secondary data) का सहारा लिया गया है, जो विभिन्न सरकारी रिपोर्ट और सर्वेक्षणों से संकलित किया गया है। मुख्य स्रोतों में सम्मिलित हैं-

- **नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) 2024 रिपोर्ट**
- **पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) – 2023**
- **कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) वार्षिक रिपोर्ट 2024**

परिकल्पनाएं

H_1:
डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कौशल विकास से रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।

H_2:
डिजिटल साक्षरता में वृद्धि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच रोजगार के अवसरों का अंतर कुछ कम हुआ है।

H_3:
डिजिटल कौशल विकास व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है।

साहित्य पुनरावलोकन(Literature Review)

Singh & Dixit (2025) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका पर जोर देते हुए बताया कि ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल ट्रेनिंग और ई-लर्निंग मॉड्यूल ने कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया है।

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE, 2024) की रिपोर्ट में 2019–2024 तक कौशल विकास पर सरकारी निवेश, लाभार्थियों की संख्या और प्रमुख कार्यक्रमों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शाता है कि डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण अधिक प्रभावी और व्यापक हुआ।

National Digital Literacy Mission (NDLM, 2024) के अनुसार भारत में डिजिटल साक्षरता दर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है, जिससे डिजिटल विभाजन कम हो रहा है और कौशल प्रशिक्षण में समान अवसर सुनिश्चित हो रहे हैं।

Periodic Labour Force Survey (PLFS, 2023) ने श्रम शक्ति की भागीदारी और डिजिटल कौशल की बढ़ती आवश्यकता को उजागर किया, जिसमें यह बताया गया कि उद्योगों में तकनीकी दक्षता और डिजिटल कौशल वाले कर्मचारियों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

SWAYAM (2025) और **NPTEL (2025)** ने डिजिटल शिक्षा के प्रारंभिक बीज और MOOCs प्लेटफॉर्म का योगदान दिखाया, जो ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराते हैं।

Coursera (2023) की रिपोर्ट में बताया गया कि ऑनलाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले युवाओं की रोजगार पाने की संभावना और कैरियर में उन्नति में वृद्धि हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल शिक्षा रोजगार-उन्मुख कौशल विकास में कारगर है।

Digital India Initiative (2024) और **e-Skill India (2024)** के अनुसार डिजिटल अवसंरचना, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास अभियानों को गति दी जा रही है, जिससे रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

"दीनदयाल उपाध्याय : विचार और दृष्टि" (अग्रवाल, 2014) – इस पुस्तक में लेखक पत्रकारिता, राजनीति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनके बहुआयामी योगदान का विवेचन किया गया है।

"भारतीय राजनीति का वैकल्पिक दर्शन" (सिंह, 2019) – इसमें यह स्थापित किया गया है कि आज भी उनकी विचारधारा भारतीय लोकतंत्र में *विकास और आत्मनिर्भरता* का मार्ग दिखाती है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय : जीवन, दर्शन और कृतित्व" (जोशी, 2001) – इस पुस्तक में दीनदयाल जी के जीवन प्रसंगों के साथ-साथ उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है।

"Integral Humanism: An Indian Alternative" (Desai, 2008) – लेखक ने एकात्म मानववाद को पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराओं की तुलना में एक भारतीय वैचारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार एवं आत्मनिर्भरता की उपलब्धियाँ-

वर्तमान युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए हैं। डिजिटल तकनीक का प्रभाव केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली, कौशल विकास, रोजगार की संभावना और आर्थिक उत्पादकता को भी सीधे प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच साक्षरता और कौशल का अंतर व्यापक है । डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास एक सशक्त समावेशी रणनीति के रूप में उभरा है। डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग जानना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की सूचना तक पहुँच, तकनीकी उपकरणों का उपयोग, ऑनलाइन सेवाओं का संचालन और डिजिटल वातावरण में आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से न केवल रोजगार-योग्य कौशल विकसित होते हैं, बल्कि यह शिक्षा के पारंपरिक

सीमाओं को तोड़कर समावेशी अवसरों का सृजन करता है।भारत सरकार ने इसे एक प्राथमिकता के रूप में लेते हुए अनेक पहलें की हैं, जिनमें नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन (NDLM), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), और डिजिटल इंडिया अभियान प्रमुख हैं। इन पहलों का उद्देश्य केवल नागरिकों को डिजिटल उपकरणों से परिचित कराना नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक रोजगार-उन्मुख कौशल से लैस करना भी है। हाल के वर्षों में हुए अध्ययनों और सरकारी रिपोर्टों से स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास का प्रत्यक्ष संबंध रोजगार की संभावनाओं और सामाजिक-आर्थिक विकास से है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती डिजिटल पहुँच ने शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोले हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में सुधार रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास का अध्ययन केवल तकनीकी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि रोजगार, समावेशिता और सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में डिजिटल साक्षरता कितने प्रतिशत रही इसे हम तालिका 1 के माध्यम से समझेंगे।

तालिका 1:

भारत में डिजिटल साक्षरता के आँकड़े

वर्ष	डिजिटल साक्षरता दर (प्रतिशत)	शहरी साक्षरता दर (प्रतिशत)	ग्रामीण साक्षरता दर (प्रतिशत)
2019	20.5	45.3	12.8
2020	25.8	50.1	15.5
2021	32.1	55.4	19.8
2022	40.7	62.3	27.4
2023	46.3	70.5	33.1
2024	38	61	25

स्रोत: नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) रिपोर्ट 2024

तालिका 1 से स्पष्ट है कि 2019 से 2024 के बीच शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की दर लगातार बढ़ती रही है। कुल डिजिटल साक्षरता दर 2019 के 20.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 46.3 प्रतिशत हो गई, जो अत्यंत उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है। तथा यह प्रगति 2024 में घटी है शहरी क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता शुरू से ही अधिक रही है, किंतु समय के साथ शहरी और ग्रामीण दोनों के बीच का यह अंतर धीरे-धीरे कम होता दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को और गति देने के लिए बुनियादी ढाँचे के विस्तार, डिजिटल उपकरणों की पहुँच बढ़ाने, तथा जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह वृद्धि न केवल बनी रहे, बल्कि और अधिक मजबूत तथा व्यापक हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिये संचालित कौशल विकास योजनाओं ने भारत में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में अत्यंत प्रगति की है। वर्ष 2014 के बाद सरकार दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चली जिसमें विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को वृहद स्तर पर प्रोत्साहित किया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त संचयी आँकड़े इस परिवर्तन की व्यापकता एवं प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। जिसे नीचे दी गयी तालिका से समझेंगे -

तालिका .2

डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख योजनाओं की उपलब्धियाँ (2014–2024-25)

योजना का नाम	प्रमुख उपलब्धि/कुल आँकड़ा
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)	7.35 करोड़ नामांकन
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	1.6 करोड़ प्रशिक्षित
स्किल इंडिया मिशन (SIM)	2.27 करोड़ प्रशिक्षित

SWAYAM	4.20 करोड़ नामांकन
FutureSkills PRIME (NASSCOM)	15.78 लाख प्रशिक्षित

स्त्रोत - कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE), NSDC, NASSCOM (FutureSkills PRIME), SWAYAM प्लेटफॉर्म एवं PMGDISHA की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट्स (2014–2024-25)।

उपरोक्त तालिका से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम यह कह सकते है कि डिजिटल कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं ने विशेष रूप से ग्रामीण भारत में सकरात्मक परिणाम रहे हैं । जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 7.35 करोड़ से अधिक नामांकन हुए जो यह दर्शाते हैं कि डिजिटल साक्षरता की सीमितिता केवल अब केवल शहरी क्षेत्रों तक नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समाज में भी प्रभावशाली स्तर पर है। 4.20 करोड़ से अधिक SWAYAM प्लेटफॉर्म पर नामांकन जो यह संकेत देते हैं कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो पाया है, जिससे शिक्षार्थियों को समय एवं स्थान की बाधाओं से राहत मिली है। प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में FutureSkills PRIME जैसी योजनाओं ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा एवं डेटा एनालिटिक्स जैसे उच्च स्तरीय कौशलों में प्रशिक्षित कर रहा है जिसने लोगों को वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार किया है। वर्ष 2014 के बाद इन प्रमुख डिजिटल पहलों के जारिए 20 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौशल प्रशिक्षण एवं डिजिटल साक्षरता से जोड़ा दिया गया है। जो यह बताती है कि यह न केवल रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक ठोस कदम भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कौशल विकास की यह प्रगति सामान्य नहीं बल्कि यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के उस विचार को साकार करती है, जिसमें उन्होंने विकास का केंद्र मानव को ही समझा है। दीनदयाल उपाध्याय कहते है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके । सरकर ने दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अत्यंत गंभीरता से लिया इसलिए सरकार द्वारा कौशल विकास पर सरकारी निवेश किया जा रहा है जिसका अध्ययन हम निम्न तालिका के माध्यम से अध्ययन करेंगे -

तालिका .3

भारत में कौशल विकास पर सरकारी निवेश (2019–2024)

वर्ष	कौशल विकास में निवेश (₹ करोड़)	लाभार्थियों की संख्या (करोड़)	प्रमुख संचालित कार्यक्रम
2019	800	0.102	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), स्किल इंडिया मिशन
2020	1,200	0.156	PMKVY, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), आत्मनिर्भर भारत योजना
2021	1,500	0.254	PMKVY, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS), डिजिटल इंडिया प्रोग्राम
2022	2,000	0.308	PMKVY, स्किल इंडिया मिशन 2.0, आत्मनिर्भर भारत
2023	2,300	0.402	PMKVY, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल इंडिया 4.0
2024	1.48 लाख करोड़	0.42	MKVY 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS), जन शिक्षण संस्थान (JSS), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) के विशेष कौशल उन्नयन कार्यक्रम

स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE), वार्षिक रिपोर्ट 2024

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 2019 से 2024 तक भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों में लगातार निवेश किया है। यह निवेश 2019 में ₹ 800 करोड़ से बढ़कर 2024 में शिक्षा,रोजगार,कौशल विकास के लिए ₹ 1.48 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो यह दर्शाता है कि सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।लाभार्थियों की संख्या भी इसी अवधि में बढ़ी, जो 2019 में 0.156 करोड़ थी और 2024 में 0.42 करोड़ तक पहुँच गई, जिससे यह साफ़ होता है कि इन योजनाओं की पहुँच लगातार बढ़ रही है। इस विकास को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), स्किल इंडिया मिशन, और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे रणनीतिक पहल

प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन निवेशों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी, भौगोलिक रूप से समुचित पहुँच सुनिश्चित करना, और सुधार हेतु फीडबैक तंत्र स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त कौशलों को स्थानीय रोजगार अवसरों, उद्योगों की आवश्यकताओं तथा उद्यमशीलता विकास से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष रूपांतरण रोजगार एवं आय वृद्धि में सुनिश्चित हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत में न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि की है, बल्कि रोजगार के पारंपरिक ढांचे में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे है। देखते ही देखते भारत की रोजगार योग्यता (Employability) में वर्ष 2022 में जो 46.2% थी वह वर्ष 2026 में 56.35% हो गई है।[1] जो यह प्रदर्शित करता है कि डिजिटल प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम का प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, देखे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी हो रही है जिसमें फ्रीलांसिंग एवं गिग इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है। जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे Upwork, Fiverr, Freelancer एवं True lancer ने गिग इकोनॉमी (अस्थायी एवं लचीले रोजगार) को एक संगठित स्वरूप दे रहे हैं।[2] आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 1.20 करोड़ हो गयी। जो वर्ष 2020-21 में मात्र 77 लाख ही थी। अनुमानतः यह कह सकते हैं कि यह संख्या वर्ष 2029-30 में 2.35 करोड़ तक पहुँच सकती है।[3] इतना ही नहीं वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट-आधारित हायरिंग में भी 38% की वृद्धि देखी गई है।[4] व्हाइट-कॉलर गिग जॉब्स की संख्या में वित्तीय वर्ष 2025 में 68 लाख थी जो वित्तीय वर्ष 2026 में बढ़कर 82.3 लाख पहुँच गयी है।[5] यह कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'स्वावलंबन एवं अपनी क्षमता के विकास' के सिद्धांत के ही अनुरूप है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यापार के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है एवं लोगों के समक्ष स्वरोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। जिसमें Amazon, Flipkart, Government e Marketplace, Meesho तथा Etsy जैसे प्लेटफॉर्म ने छोटे उत्पादकों एवं उद्यमियों के लिए व्यापक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। परिणामस्वरूप GeM पोर्टल जिस पर 60 लाख से अधिक विक्रेताओं ने पंजीकरण किया है। जो सीधे सरकारी संस्थानों को अपने उत्पाद विक्रय कर पा रहे हैं।[6] इतना ही नहीं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 37 लाख से अधिक गिग वर्कर्स कार्य कर रहे हैं।[7] डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मात्र कौशल विकास में ही वृद्धि नहीं की है बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के माध्यम से प्रशिक्षित 'लखपति दीदियाँ' Meesho एवं Amazon Karigar जैसे प्लेटफॉर्म के द्वारा अचार, हस्तशिल्प आदि उत्पाद बेचकर वार्षिक ₹1-2 लाख या उससे अधिक की आय का अर्जन कर रही हैं।[8] यह प्रवृत्ति 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर अग्रसर है। जिसमें उत्पादक को सीधे बाजार से जोड़ा गया और मध्यस्थों की भूमिका को न्यूनतम कर दिया गया है। डिजिटल तकनीक ने दूरस्थ कार्य (Work from Home) को भी आसान बना दिया। जिसमें लोग अब Zoom, Google Meet, Microsoft Teams एवं Slack जैसे उपकरणों से घर बैठ कर आय का सृजन कर रहे हैं। फरवरी माह 2026 में पूर्णकालिक दूरस्थ तकनीकी नौकरियों में 67% की वृद्धि हुई।[9] टियर-2 शहरों[10] में गिग हायरिंग का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2026 में 30.7% रहा है जो वित्तीय वर्ष 2027 में बढ़ाकर 38.8% होने का अनुमान है।[11] डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दूरस्थ कार्य को आसान बना दिया है अब व्यक्ति अपने स्थानीय क्षेत्र में रहते हुए भी वैश्विक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिससे न केवल बचत में बढ़ोत्तरी होती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। यह अवधारणा 'एकात्म मानववाद' सिद्धांत का ही रूप है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक संतुलन को भी ध्यान में रखा जा रहा है

[1] India Employability Report 2026 तथा India Skills Report 2022-23, Wheebox द्वारा प्रकाशित मानक रिपोर्ट्स।

[2] NITI Aayog. (2022). *India's Booming Gig and Platform Economy: Perspectives and Recommendations on the Future of Work*; *Freelancing in India 2025* (Indeed & PayPal).

[3] Ministry of Finance, Government of India. *Economic Survey 2025–26*; Boston Consulting Group (BCG) & NITI Aayog. *India's Gig Economy Outlook 2030*.

[4] CIEL HR Services. *Flexible Talent Report 2026*; Microsoft & LinkedIn. *Future of Work in India 2026*.

[5] Indeed & BankBazaar. *White-Collar Gig Economy Monitor FY 2025–26*; Naukri JobSpeak (February 2026 issue).

[6] Government e Marketplace (GeM). *Annual Report 2025–26*: "6 million+ local vendors registered."

[7] Indian Institute of Management Bangalore (IIMB) & Better Place Labs. *State of India's Gig Economy 2026*

[8] MeitY. *PMGDISHA Impact Assessment Report 2025*; Ministry of Rural Development. *Lakhpati Didi Scheme Progress Report 2025–26*; Amazon India. *Amazon Karigar Case Study* (2026)

[9] MeitY (2025). *PMGDISHA Impact Assessment Report*; Ministry of Rural Development (2025–26). *Lakhpati Didi Scheme Progress Report*; Amazon India (2026). *Amazon Karigar Case Study*.

[10] टियर-2 शहर (Tier-2 Cities) से आशय भारत के उन मध्यम आकार के शहरों से है जो मेट्रो शहरों की तुलना में कम विकसित होते हैं, परंतु तेजी से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास कर रहे होते हैं; जैसे—इंदौर, कोयंबटूर, लखनऊ, जयपुर, वडोदरा आदि

[11] BetterPlace & Naukri. *Tier-2 Cities Hiring Report: Gig Work Edition* (FY 2025–27 projections

परिणाम और विवेचना –

किसी भी शोध में उद्देश्यों की पूर्ति और परिकल्पना का सिद्ध होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रस्तुत शोध में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति एवं परिकल्पना की जांच हेतु हेतु विभिन्न सरकारी रिपोर्टों एवं सर्वेक्षणों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके अनुसार कौशल विकास, व्यक्ति को न केवल रोजगार बल्कि स्व-रोजगार के लिए भी सक्षम बना देता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तथा अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर के उन्हे आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करता है। यह विश्लेषण डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों एवं आत्मनिर्भरता पर इनके प्रभाव को समझने पर है।

उद्देश्य 1: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा में अंतर एवं प्रगति का अध्ययन

उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात यह ज्ञात होता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच आसान एवं संसाधन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हैं, इसके पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार है लेकिन शहरों की अपेक्षा कम है। परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रीय असमानता की समस्या अभी भी विद्यमान है,लेकिन उसमें धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है, जो समावेशी विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

उद्देश्य 2: ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल ट्रेनिंग, ई-लर्निंग मॉड्यूल और मोबाइल एप्स किस प्रकार युवाओं को कौशल विकसित करने और रोजगार के लिए तैयार करने में सहायक हैं

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल प्रशिक्षण, ई-लर्निंग मॉड्यूल एवं मोबाइल एप्स ने कौशल अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को अत्यंत सुलभ एवं लचीला बना दिया है।जिससे अब युवाओं को समय एवं स्थान की बाधाओं से मुक्त मिली और कहीं भी कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि देखने को मिली है। डिजिटल शिक्षा ने कौशल विकास के अवसरों का लोकतंत्रीकरण कर दिया है।

उद्देश्य 3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), Skill India Mission, e-Skill India, SWAYAM आदि कार्यक्रमों का रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन

विभिन्न अध्ययन यह बताते है कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों जैसे Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Skill India Mission, e Skill India, SWAYAM का अत्यंत व्यापक प्रभाव रहा है। इन योजनाओ के माध्यम से कौशल विकास में वृद्धि देखी गयी है । जिससे उनकी कार्यक्षमता तो बढ़ी ही है और साथ ही रोजगार एवं स्व रोजगार के नए अवसरों में भी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी, ई-कॉमर्स एवं दूरस्थ कार्य जैसे नए अवसरों का सृजन हुआ है। जिससे युवाओं के लिए रोजगार के विकल्पों में भी विविधता आई है।

उद्देश्य .4 डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार सृजन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' सिद्धांत का विश्लेषण करना

अध्ययन के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि डिजिटल कौशल विकास ने व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा की ओर प्रेरित किया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति का समग्र विकास एवं आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने और आत्मनिर्भर बनाने दोनों पर ही बल दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने तथा स्थानीय स्तर पर रहते हुए आर्थिक उन्नति करने का अवसर प्रदान कर रहा है ।यही इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देता है।

परिकल्पना परीक्षण

H_1: **डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कौशल विकास से रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव रहा है।**
अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों का सकरात्मक प्रभाव रहा है। प्रशिक्षण उपरांत यह देखने में आया कि रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं तथा युवाओं की रोजगार-योग्यता में वृद्धि हुई है। अतःइस H_1 परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

H_2: **डिजिटल साक्षरता में वृद्धि से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच रोजगार के अवसरों का अंतर कुछ कम हुआ है।**

अनेकों रिपोर्टों विभिन्न आंकड़ों के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच रोजगार के अवसरों के अंतर में कुछ कमी आयी है। जिससे यह H2 परिकल्पना स्वीकृत होती है।

H_3: डिजिटल प्लेटफॉर्म कौशल विकास व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाकर 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है।

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि डिजिटल माध्यमों ने स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता में वृद्धि की है परिणामस्वरूप आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि देखने को मिली है। कौशल से लेश व्यक्ति रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु अग्रसर होते हैं। परीणामस्वरूप वह खुद का भी विकास करते है साथ ही वह दूसरों के लिए भी विकास के नए मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रवृत्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत के अनुरूप ही है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र एवं संतुलित विकास पर बल दिया जाता है। अतः यह H_3 परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

विवेचना (Discussion)

शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित कौशल विकास और रोजगार सृजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत से अत्यंत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए है, क्योंकि यह सिद्धांत व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। जब व्यक्ति डिजिटल माध्यम से कौशल का अर्जन कर लेता है तो वह रोजगार एवं स्व-रोजगार दोनों ही अवसर प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनता है साथ ही अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। जिससे समाज और राष्ट्र के संतुलित एवं समावेशी विकास को बल मिलता है।परिणस्वरूप देखते ही देखते डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास के प्रति समाज में लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। वर्तमान समय में रोजगार, कौशल अधिग्रहण एवं आर्थिक व्यवहार तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित होते दिख रहें हैं। मुख्यतः यह देखने में आया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुरूप ही अवसर प्रदान किए हैं। जिससे आज का युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है।

चुनौतियाँ

भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म कौशल विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसरों का हो रहा है परंतु इतने सकारात्मक प्रभाव के बावजूद कुछ बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं—

- डिजिटल उपकरणों की कमी
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुँच
- डिजिटल साक्षरता का अभाव
- पारंपरिक नियोक्ताओं में ऑनलाइन प्रमाणपत्रों को लेकर संदेह
- उपकरणों—लैपटॉप, स्मार्टफोन—की सीमित उपलब्धता।
- बिजली आपूर्ति की अनियमितता।
- डिजिटल साक्षरता में असमानता।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमाणपत्रों की मान्यता का अभाव
- तकनीकी समस्याएँ (सर्वर, ऐप क्रैश, कनेक्टिविटी इश्यू)

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट पहुँच और उपकरणों की सुलभता को और मजबूत करना आवश्यक है। हालाँकि, भारत की युवा आबादी, बढ़ती तकनीकी क्षमता, सरकार-निजी क्षेत्र के सहयोग तथा डिजिटल कौशल की वैश्विक मांग को देखते हुए, डिजिटल शिक्षा भारत को

वैश्विक कौशल-हब बनाने की क्षमता रखती है। यह यात्रा केवल सीखने की प्रक्रिया का परिवर्तन नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य कार्यबल की संरचना को भी नया रूप देने वाली है।

निष्कर्ष

भारत में डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों की भूमिका अत्यंत निर्णायक और बहुआयामी रही है। 2019 से 2024 के बीच डिजिटल साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, साथ ही कौशल विकास पर सरकारी निवेश और लाभार्थियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी गई। डिजिटल माध्यमों ने शिक्षा और प्रशिक्षण को अधिक सुलभ, लचीला और समावेशी बनाया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवसरों की समानता बढ़ी है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों ने युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया, रोजगार-उन्मुख कौशल सिखाने में मदद की और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा, COVID-19 महामारी के दौरान इन प्लेटफ़ॉर्मों ने शिक्षा और प्रशिक्षण की निरंतरता सुनिश्चित कर यह सिद्ध किया कि डिजिटल माध्यम न केवल वैकल्पिक हैं बल्कि भविष्य की शिक्षा और कौशल विकास की रीढ़ भी है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आधारित कौशल विकास की यह प्रक्रिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत का वास्तविक एवं व्यावहारिक स्वरूप का प्रदर्शन करती है। यह प्रक्रिया कोई सामान्य नहीं बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए उसे कौशल, रोजगार एवं स्व-रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाती है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों के द्वारा प्राप्त कौशल व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं कि वह स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के नए -नए अवसरों का सृजन कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. Agarwal. (2014). Deendayal Upadhyaya: Vichar aur drishti.
[2]. Coursera. (2023). Global skills report 2023.
[3]. Desai, A. (2008). Integral humanism: An Indian alternative.
[4]. Joshi, S. (2001). Pandit Deendayal Upadhyaya: Jeevan, darshan aur krititva.
[5]. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2024). Annual report 2023–24. Government of India.
[6]. National Digital Literacy Mission. (2024). NDLM progress report.
[7]. National Skill Development Corporation. (2024). Skill development report.
[8]. National Statistical Office. (2023). Periodic labour force survey (PLFS).
[9]. NASSCOM. (2024). FutureSkills PRIME report.
[10]. Singh, R. (2019). Bhartiya rajneeti ka vikalpik darshan.
[11]. Digital India. (2015). Government of India.
[12]. Skill India Mission. (2015). Government of India.
[13]. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. (2015). Government of India.
[14]. SWAYAM. (2017). Government of India.
[15]. NPTEL. (2025). Course statistics.
[16]. पंडित दीनदयाल उपाध्याय. (1965). Ekatma manavvad (lectures).
[17]. BetterPlace & Naukri.com. (2026). Tier-2 cities hiring report: Gig work edition (FY 2025–27 projections).
[18]. Boston Consulting Group & NITI Aayog. (2025). India's gig economy outlook 2030.
[19]. CIEL HR Services. (2026). Flexible talent report 2026.
[20]. Indeed & BankBazaar. (2026). White-collar gig economy monitor (FY 2025–26).
[21]. Indeed & PayPal. (2025). Freelancing in India 2025.
[22]. Indian Institute of Management Bangalore & BetterPlace Labs. (2026). State of India's gig economy 2026.
[23]. Ministry of Electronics and Information Technology. (2025). PMGDISHA impact assessment report.
[24]. Ministry of Finance. (2026). Economic survey 2025–26. Government of India.
[25]. Ministry of Rural Development. (2026). Lakhpati Didi scheme progress report 2025–26.
[26]. Microsoft & LinkedIn. (2026). Future of work in India 2026.

[27]. NITI Aayog. (2022). India's booming gig and platform economy: Perspectives and recommendations on the future of work.
[28]. Naukri.com. (2026, February). JobSpeak report.
[29]. Government e Marketplace. (2026). Annual report 2025–26.